17.55 hrs.

DISCUSSION *RE*. SUGAR POSITION AND CANE PRICE

[SHRI VASUDEVAN NAIR *in the chair*]

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरोना) : चेयरमेन साहब, मैं पहले तो शुगर की समस्यायें क्या हैं उनको बताना चाहता हूं और फिर एक एक के बारे में मेरे सुझाव क्या है वह बताऊंगा। पहली बात ता यह है कि जो 7 रुपये 37 पैस फी क्वीटल गन्ने का दाम फिक्स किया गया है वह क्या उचित है? दूसरे बैंक्स चीनी के निमित्त जो एडवान्स दे रहे हैं क्या वह इतना पर्याप्त है कि जिससे गन्ने का दाम दिया जा सके? तीसरा है वेज बोर्ड। चौथा है डेवलपमेंट। पांचवें जो सरप्लस शुगर है उसके लिए क्या समाधान होगा? फखरुद्दीन साहब यहां पर बैठे हुए हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शुगर इन्डस्ट्री की यही समस्या है जैसे कि एक शेर है :—

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की
मर्ज बढ़ता गया, ज्यों ज्यों दवा की।

करीब 36 वर्ष से ये शुगर कन्ट्रोल बोर्ड और विभिन्न संस्थायें बनाई गई चीनी के सम्बन्ध में कि जो समस्यायें है उनका निराकरण कैसे हो लेकिन एक ही समाधान उन्होंने पाया और वह यह कि जब चीनी ज्यादा पैदा हो तो गन्ने का दाम कम कर दो और जब चीनी कम पैदा हो तो गन्ने का दाम बढ़ा दो। चीनी की समस्या के समाधान के निमित यही बात सामने आती रही है। मैं बताना चाहता हूं कि 1967-68 में इस देश में चीनी बहुत कम हुई और एक समस्या देश के सामने पैदा हुई। उस समय चीनी 4 रुपए से लेकर 6 रुपए किलो तक बिकने लगी। उसके बाद सोचा गया कि क्या उपाय किया जाये। किसानों को प्रेरित करने के लिए कि वे ज्यादा गन्ना पैदा करें, यह जरूरी था कि उनको गन्ने का दाम ज्यादा मिले। उस समय बाबू जगजीवन राम जी के पास यह विभाग था। उन्होंने उसका एक समाधान ढूंढा। पहले तो यह होता था कि जब चीनी कम हो तो कंट्रोल लगा दो और जब चीनी ज्यादा हो तो डी-कंट्रोल कर दो। उन्होंने एक नयी चीज निकाली—पार्शियल डी-कंट्रोल। उनका मतलब था कि पार्शियल डी-कंट्रोल में जो फ्री शुगर थी वह बाजार में ज्यादा दाम पर बिकेगी और मिलें उस अधिक दाम से किसानों को गंने का ज्यादा दाम दें ताकि किसान उसकी तरफ प्रेरित हों और ज्यादा गंना पैदा करें। इस नीति ने 1968-69 में काफी काम किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चीनी की कमी थी तब तो इसने काम किया लेकिन जब चीनी की बहुतायत हो गई फिर भी वही आपकी पार्शियल डी-कंट्रोल की पालिसी चल रही है तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज फ्री शुगर और लेवी शुगर की करीब करीब प्राइस बराबर है। इस साल भी बावजूद इसके कि गवर्नमेंट कहती थी कि हम ज्यादा दाम दिलायेंगे लेकिन किसानों को 7 रुपये 37 पैसे से ज्यादा नहीं मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो गंना बोया गया था उसमें ज्यादा सोईंग नहीं हुई और आप देखेंगे, मेरा ऐसा अनुमान है कि करीब करीब 15-20 फीसदी चीनी कम पैदा होगी। और जब उत्तर भारत में चीनी कम पैदा होती है तो उसका असर पूरे भारतवर्ष पर पड़ता है और फिर आप देखेंगे कि गंने का दाम बढ़ा दिया गया है ताकि किसान ज्यादा गंना पैदा करें। सोचने की बात है कि गंने के दाम के उतार बढ़ाव में होता यह है कि गंना किसी साल तो ज्यादा हुआ और किसी साल कम हुआ। क्या आपकी मिनिस्ट्री और आपके जो एक्सपर्टस हैं वे इस बात का प्रयत्न नहीं कर सकते कि कोई ऐसा समाधान निकाले जिससे कि फैक्टरियों को गंना मिलता रहे और किसानों को तकलीफ न हो

बल्कि उनको इस बात की प्रेरणा मिले कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना पैदा करते रहें ? या कम से कम इतना गन्ना पैदा करें जितना कि मिलों को जरूरत हो।

मैंने देखा है कि पहले गांवों में जो लोग दूध में गुड़ डालते थे आज वे गुड़ के शौकीन दूध में सफेद चीनी डाल कर पीते हैं। इस तरह से इसका कंजम्शन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसका कि फार रीचिंग, आगे आने वाले समय पर अच्छा प्रभाव पड़े। चीनी का उत्पादन हर साल करीब करीब बराबर हो, इस तरह का कोई भी उपाय आज तक नहीं किया गया है। दूसरी बात यह कि जो चीनी मिलें चालू हैं उनके पास लगभग 20 लाख टन चीनी स्टाक में है जो कि अभी बिकनी है। और अब आपका अनुमान है कि 40 लाख टन चीनी बनेगी, हालांकि वह बनेगी नहीं यह मैं आपको बता रहा हूं। इतना स्टाक होने पर गन्ने का दाम तभी दिया जा सकता है जबकि सीजन भर में जो चीनी बने वह तुरंत बिकती जाये। लेकिन यह चीज इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में चीनी की कितनी डिमाण्ड है। या फिर दूसरी बात यह है कि बैंक्स इतना एडवांस दें कि जिससे गन्ने का दाम दिया जाता रहे। पिछले साल 42 लाख टन चीनी बनी और अब करीब 40 लाख टन बनेगी तो उसके लिए बैंकों को करीब करीब 400 करोड़ रुपये से ऊपर एडवांस देना चाहिए लेकिन पिछले साल बैंक्स ने करीब 200 करोड़ से कुछ ऊपर एडवांस दिया है। इसका स्वाभाविक नतीजा यह था कि गन्ने के दाम नही दिये जा सके और आगे और भी बकाया पड़ने वाला है। क्योंकि इस वक्त जो चीनी स्टाक में है उसका इन्ट्रेस्ट बढ़ता जायेगा और वह चीनी के प्रोडक्शन पर दबाव डालेगा। इस लिए मैं यह चाहता हूं कि किसान को उत्साहित रखने के लिए जरूरी है कि सीजन के अंदर ही उस के गन्ने के दाम मिल जायें, चाहे आप इस के लिए जो भी उपाय निकालें।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं वेज बोर्ड के सम्बंध में। शुगर इंडस्ट्री में आज एक बात है कि पूरी कंट्री के लिए दो वेज बोर्ड बन चुके हैं, क्योंकि पूरी कंट्री की शुगर फैक्ट्रियां वेज बोर्ड से प्रभावित थीं। सारी चीजें यहां तय होती है। गन्ने के दाम आप तय करें, चीनी के दाम आप तय करें, मेनुफैक्चरिंग कास्ट आप तय करें। कोई चीज ऐसी नहीं है जो बाहर तय होती हो। वेज बोर्ड ने यह सिफारिश की कि जो इंसिडेंस इस की वजह से पड़ेगा, शुगर प्राइस रिवीजन में उस का भी खयाल रक्खा जायेगा। वह रिपोर्ट आई। आप के विभाग ने भी देखा, लेबर मिनिस्ट्री ने भी देखा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी देखा और सब ने स्वीकार किया। किसी का कमेंट नहीं है कि वेज बोर्ड उचित रूप से तय नहीं करता। लेकिन इस के बावजूद चूंकि शुगर प्राइस में रिवीजन नहीं हुआ, इस लिए वेज बोर्ड की सिफारिशें, जो 1 नवम्बर, 1969 से लागू होनी चाहिए थीं, लागू नही हुई। वह 1970 से लागू हो रही हैं। नतीजा आप के सामने है। अभी जूट मिलों के दो लाख मजदूरों ने हड़ताल किया है और गवर्नमेंट और सारे हिंदुस्तान में परेशानी है। अगर शुगर फैक्ट्रियों के मजदूर अपना बकाया नहीं पायेंगे वेज बोर्ड के हिसाब से तो निःसंदेह उन का कंट्री वाइड स्ट्राइक होगा, इस को कोई रोक नहीं सकता। इस लिए जरूरत इस बात की है कि जल्दी से इस का कोई समाधान ढूंढ कर निकाला जाये और उस की घोषणा की जाये।

18 hrs.

मेरे खयाल से जो चीनी के उत्पादन का सर्प्लस है उस समस्या को दो ही तरह से आप हल कर सकते है। एक तो यह कि आप अपने एक्सपोर्ट

[श्री कांशीनाथ पाण्डेय]

को बढ़ाइये और दूसरे यह कि आप एक बफर स्टाक क्रिएट कीजिये । किस तरह से आप करेंगे, यह लम्बी चीजें है, डिटेल्स की बातें है, लेकिन आप को करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के लिये यह उचित भी है क्योंकि आगे का जो ट्रेंड है जो (पालिसी) है, उस से चीनी कम पैदा होगी और अगर आप के स्टाक में चीनी रही जब चीनी के दाम ऊपर उठें तो आप उस बफर स्टाक से मार्केट में चीनी भेज सकते हैं और उस के दामों में सन्तुलन बाजार में रख सकते हैं ।

एक चीज और कहना चाहता हूँ खास तौर से कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने हाल ही में यह मिनिस्ट्री ली है । वह सिंसिअर आदमी हैं । एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट शुगर इंडस्ट्री की उन के अंडर है । हजारों करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी के लिए और मेरा खयाल है कि कई जहार करोड़ रुपये स्टेट्स को इस इंडस्ट्री ने पर्चेज टैक्स में दिये । लेकिन उत्तर भारत की मिलों में प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ सका । क्यों ? आप को इस के लिए उपाय करना चाहिये था । महाराष्ट्र में, आंध्र में, मैसूर में, उड़ीसा, में मद्रास में गन्ने की उपज बढ़नी है क्योंकि सभी जगहों पर सिंचाई के पूरे साधन है । महाराष्ट्र में 30 मर्तबे पानी देते हैं और उत्तर भारत में तीन मर्तबे भी पानी देने की व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में आप कैसे समझ सकते हैं कि उन के मुकाबले में हमारे यहां उत्पादन हो सकेगा । यदि आप ने कुछ भी ध्यान इस तरफ दिया होता, यहां ऐसी व्यवस्था होती जिस से किसानों को पूरी मात्रा में पानी मिलता, और दूसरी चीजें मिलतीं—खाद की बात छोड़िये, वह तो अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग डालेंगे ही, लेकिन पानी सब से आवश्यक है—तो गन्ने की पैदावार अच्छी होती । जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप कैसे किसी को दोष दे सकते हैं इस के लिए ? आप के यहां कौंसिल बनी हुई है जिस का नाम है डेवेलपमेंट कौंसिल फार शुगर इंडस्ट्री । लेकिन मैं कह सकता हूँ । that it is a bogus Council. It sits once in a year. It decides nothing and does nothing. I do not know why it has been created.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेम्बर कौन हैं ?

श्री काशी नाथ पाण्डेय : गवर्नमेंट के आफिसर हैं, सभी सेक्रेट्री हैं चेयरमैन सेक्रेटरी हैं इस लिए इस कौंसिल की सिफारिशों को कोई सुनता नहीं है । अगर कोई मिनिस्टर रहा होता तो उसी रिकमेन्डेशनों पर जरूर ध्यान दिया जाता । यह केवल एक उपेक्षित भाव ही है । आप समझ लीजिये कि सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे । जो आप चाहेंगे वह कहेंगे । लेकिन उन को सूचना देनी चाहिए कि इस कौंसिल में किन-किन बातों पर बहस हुई और क्या निष्कर्ष निकला । लोगों के सुझाव क्या थे । अगर वह आप की नोटिस में आते और आप के पास वक्त होता उन को सुनने का जो यह समस्या नहीं रहती ।

इस कौंसिल का कैसे निर्माण हो इस बात का भी खयाल रक्खा जाना चाहिए । यह रफी साहब के जमाने में बनी थी । मैं मजदूरों की तरफ से शुरू से इस का मेम्बर था । पहली मर्तबा इस का उद्‌घाटन रफी साहब ने किया था, डेवलपमेन्ट काउन्सिल का रोका सारे देश में था कि डेवेलपमेंट कौंसिल है भाई । रफी साहब इस के प्रधान रहे । लेकिन उन के बाद से सेक्रेटरी साहब होगये । अब सेक्रेटरी साहब को कोई पूछना नहीं है कौंसिल में । मैं समझता हूं कि इस बात पर भी आप का ध्यान जाना चाहिए ।

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : सभापति महोदय, चीनी की पैदावार से सरकार को कितने

पैसे की आमदनी है इस कोशा यद बहुत से लोग नहीं जानते। एक एकड़ जमीन में जो केन पैदा होता है उस से प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार को मिला कर कम से कम 500 रु० टैक्सेज का मिलता है, और इनना ही बड़ी फैक्ट्री वालों और कोआपरेटिव वालों को भी मिलता है। यह नहीं है कि नहीं मिलता है। लेकिन मैं सरकार के लिए कह रहा हूं जिस की बात हो रही है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इतनी फायदेमन्द इंडस्ट्री की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

अभी तक 1970-71 के लिए जो शुगर पालिसी है उस का एलान नहीं किया गया है कि कंट्रोल रहेगा या डिकंट्रोल रहेगा अथवा पार्शल कंट्रोल रहेगा या कैसे क्या होगा। इस लिए मेरा पहला निवेदन है कि पालिसी का एलान होना चाहिए। जहां तक मेरा अपना खयाल है आज शुगर की 40 लाख टन की पैदावार 1970-71 में होने जा रही है। 21 लाख टन आर का कैरी ओवर होगा। इस तरह से 61 लाख टन जो होगी वह शुगर आप को मिलने वाली है। दो या ढाई लाख टन तो एक्सपोर्ट की जायेगी, बाकी इंटर्नल कंजम्शन 29 या 30 लाख टन होगा। इस से ज्यादा नही है। अगर हम इस को 30 लाख टन भी मान लें और ढाई लाख टन एक्सपोर्ट का। इह तरह से कुल 32-33 लाख टन हुआ। 61 लाख टन में से 33 लाख टन निकल जाये तो भी आप 35 लाख टन के नीचे ही रहेंगे। बाकी शुगर आर के गोदामों में पड़ी रहेगी। इतने बड़े स्टाक का आप कैसे इन्तजाम कीजियेगा, इस पर आप को ध्यान देना चाहिए। इस लिए मेरा सुझाव है कि आप शुगर को डिकंट्रोल कर दीजिये जिस में ज्यादा रिस्पोंसिबिलिटी गवर्नमेंट पर न रहे।

जहाँ तक शुगर के बफर स्टाक का सवाल है, सेन कमिशन ने इस के लिए रिकमेन्डेशन की है कि बफर स्टाक आप के पास इस लिए रहना चाहिए कि अगर मार्केट में लोगों ने चीनी को दबा लिया और उस की ब्लेक मार्केटिंग होने लगी तो उस को आप रिलीज कर सकते हैं और जनता को ब्लेक मार्केट से राहत से सकते हैं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। हम लोग जो खुद ग्रोअर्स हैं, उन की दिक्कत यह है कि हमारे गन्ने की कीमत समय पर हम को नही मिलती है। अभी तक हम लोगों की दो-दो, ढाई ढाई लाख पहले तक की कीतत बाकी है। जिन मिलों को आप ने टेक ओवर कर लिया है उन के अन्दर भी ग्रोअर्स को कीमत नहीं मिल पाई है। इस का एक कारण है। चीनी एक ऐसी वस्तु है जिस की पैदावार की जिम्मेदारी आप के पास नही है। अगर कोई एक छटांक चीनी भी पैदा कर लेता है तो उस की मालिक सरकार हो जाती है। बिना उस की आज्ञा के न शुगर निकल सकती है और न मार्केट में जा सकती है। रह गई बात इस की कि दूसरों को पेमेंट कहां से करते हैं, तो पेमेंट बैंकों से ले कर करते हैं। हिसाब लगा कर मुझे बताया गया है कि इस साल साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। 36 लाख टन की पैदाबार अप्रैल मई तक हो जाएगी। जानकार लोगों का कहना है कि साढ़े चार सौ करोड़ रुपया अगर एडवांस का दिया जाएगा तब जा कर केन की प्राइस लोगों को दी जा सकेगी। मुझे पता नहीं यह आंकड़ा कहाँ तक सही है। लेकिन अगर इतना एडवांस नहीं दिया गया तो हो सकता है कि मजदूरों की जो मजदूरी है वह भी समय पर न मिल सके। इस वास्ते बैंक एडवांस की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये।

ग्रोअर्ज के नाते हम लोगों का अनुभव यह है कि यह इंडस्ट्री ऐसी है जिस का कोई ठिकाना नहीं है। पांडे जी ने भी यही बात कही है। हर दूसरे तीसरे साल के बाद

[श्री क० न० तिवारी]

चक्कर चलता है और कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, कभी लेस प्रोडक्शन हो जाता है और कभी अंडर प्रोडक्शन हो जाता है और यह सिलसिला चलता रहता है। जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो शुगर फैक्ट्री वाले केन नहीं लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मिलें अप्रैल, मई, जून जुलाइ तक ही चलती हैं। गर्मियों में किसान परेशान हो जाता है और किसान को लाखों मन गन्ना अपने यहां खेत में जला देना पड़ता है। इस स्थिति से परेशान हो कर वह केन का प्रोडक्शन कम कर देता है। जब वह ऐसा कर देता है तब आप शुगर केन की प्राइस बढ़ा देते हैं और मिल मालिक भी हमारे पास दौड़ते आते हैं कि हमें गन्ना दे दो, हमें दे दो। उस वक्त पोचिंग होता है, झगड़े होते हैं और कोर्ट में मुकदमे भी होते हैं। इस वास्ते कोई पालिसी आपकी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिये कि जरूरियात कितनी है, और प्रोडक्शन कितना होना चाहिये इस सब का प्लानिंग होना चाहिये। इस ओर आपका और प्रान्तीय सरकारों का भी ध्यान जाना चाहिये।

डिवेलेपमेंट की बात का जहां तक सम्बन्ध है मैं उस में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर कभी इसका वक्त मिलेगा। लेकिन दो बातों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो जहां तक कीमत का सवाल है, जैसा कानून है चौदह दिन के अन्दर उनको कीमत मिल जानी चाहिए और वह तभी मिलेगी जब बैंक उनको एडवांस करेंगे। साथ ही बफर स्टाक के बारे में तय हो जाना चाहिए कि कितना बफर स्टाक आप रखेंगे। साथ ही इस बात का एलान भी हो जाना चाहिए कि आप डिकंट्रोल करेंगे या कंट्रोल जारी रखेंगे। मेरा सुझाव है कि आप डिकंट्रोल करें शुगर को। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूरा इसको आप कंट्रोल कर लीजिये, और सारी जिम्मेदारी आप लीजिये। कोई भी नीति आप अखत्यार करें, लेकिन उसका एलान हो जाना चाहिए। मिल मालिकों को और हमें भी इस पालिसी के बारे में मालूम हो जाना चाहिए।

आपने वादा किया था कि 1969-70 में जो चीनी पैदा हुई है उस में से जो चीनी बची रह जाएगी, उसकी कीमत आप तय कर देंगे। जो उनके गोडाउंज में पड़ी रह जाएगी, जो नहीं निकलेगी, उसके बारे में कुछ ऐसा नियम था कि आप उसके दाम तय कर देंगे। वह भी आज तक आपने नहीं किया है। मेहरबानी करके इसके ऊपर भी आप विचार करें। मैंने सुना है कि डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट उसके बारे में दे दी है और वह आपके अंडर कंसिड्रेशन है। उस पर विचार करके जो आपकी नीति है, उसका एलान भी आपको कर देना चाहिये।

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur) : Mr. Chairman, Sir, if one were to examine even briefly the progress achieved in the matter of production of sugar in the last two or three years, one would find if ever a proof was needed, that a sensible policy of de-control and liberalisation and timely and adequate help given to the farmers on the one side and to the industry on the other can certainly produce larger spectacular results, as would be absolutely evident from the table of production of sugar for the last two or three years that we have in our hands. When we consider an industry on a long-term basis—and I consider it essentially an industry—we have to consider the integrated aspects of the marriage between agriculture and industry, and therefore the welfare to the working class, the workers of the sugar industry as well as the agriculturist labour are intimately connected with it, and unlesss the Government of India through the agencies of the State Government and other agencies involved have a well-integrated long-term development plan for sugar, and for that matter for any other important commodity, the progress that we have achiev-

ed for the last two or three years is not likely to be commensurate with the potential that we have in our hands.

As you would know, the Government used to declare the sugar policy of every year for the last several years in the months of July-August or definitely before September so that all components engaged in this national endeavour knew exactly where they stood. For the first time this year, I do not know for what peculiar reasons—may be, there was a great deal of sweet-bitter turmoil in the Gangetic plains of UP and Bihar or may be there were some other considerations—his announcement has been withheld. If you look at it from the national point of view, if there were any political considerations to withhold the announcement and the concretisation of the sugar policy, it is unfortunate. If it is for some other reasons, it is also equally unfortunate because at once it comes to the forefront and the limelight that no section which is engaged in this particular endeavour can know for certain in advance as to what its planning, budget, capacity and production are going to be. Therefore I would like a clear answer as to what were the special considerations that have compelled this Government to withhold the announcement of the sugar policy for the first time in recent history. This is like a rudderless ship because nobody knows what the situation is or what your Government's policies are going to be.

This particular industry has seen, unfortunately, large spells of shortages as well as surpluses. Shortages create their own peculiar problems in this country. Now, for the first time surpluses, which are a healthy thing from an overall point of view, if not handled properly are likely to become a problem to the Government in particular. I am told that we have a carry-over stock from last year of about 21 lakh tonnes and we shall have larger supplies when this particular season is over. Therefore you have to take steps in advance as to how to manage this surplus.

I have been discussing this matter with Annasahib even a year ago that as far as exports of this sugar are concerned, no client of yours in any forign country is going to weigh or be influenced by your own indigenous shortages of surpluses. He is not concerned at all. International marketing cannot be dictated by either the political policies or the actual availability situation in the country. Therefore, unless you keep up your international quota commitments according to your sugar quota and also at times like this unless you buy or take on loan sugar export quotas from other countries, you are not likely to be able to manage your surpluses.

Therefore, whether it is by way of making available this sugar at international prices to some other manufacturers, who can then later on exporting these products, or if it is the question of exporting your own quota, these things will have to be thought of in an integrated and realistic manner if the situation is not be allowed to get out of your hands.

A great deal about the future of this industry also depends upon the internal consumption. For a long period of time this country was attuned or asked or coerced by force of circumstances as well as by shortages not to cousume sugar. Either by force of circumstances and in a few cases even on a voluntary basis, people used to deny themselves the consumption of sugar. Now that the period has changed and the tide has turned, we have to see that not only as a result of the policies of Government but also as a result of the people's own dietary habits, they are encouraged to consume more and more sugar. This should also be reflected in the monthly quotas.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH (Parbhani) : Diabetic habits ?

SHRI N. K. SOMANI : Diabetics is the end result if you have an excess, Shri Shivajirao.

SHRI PRAKASH VIR SHASTRI (Hapur) : Shri Shivajirao is alert.

SHRI N. K. SOMANI : He is allergic or alert, I do not know.

Therefore a situation has now arisen that there is no further justification of this differential rate of excise that you take on

[Shri N. K. Somani]

free sugar and on levy sugar. It had a meaning and a rationale about two or three years ago when the country was undergoing critical shortages. Thanks to an imaginative and bold policy undertaken by the then Food and Agriculture Minister, we are now in this happy situation. But now when the circumstances have completely changed, the differential attitude is not justified. Whether the ratio is 70:30 or 60:40 does not make a great deal of difference to me. This has got to be taken into account so that there is continuous and healthy development of the industry.

This brings me to another point which has been ably covered by two distinguished Members who preceded me and that is that in any given commodity, in any modern international economic practice, whenever there is a temporary excess or surplus, then the Government of that country makes a buffer stock so that during the rainy period or during the lean period we can always withdraw from the buffer-stock. Apart from that, it is a healthy economic consequence so that you could support the total effort. Whether it is a buffer-stock of copper in the United States or of wheat in Canada or in other parts of the world or, for that matter, of sugar here, it stands to reason that whenever we have such surplus and suddenly we find that the market cannot aborb it, it is the bounden duty of the Government to create a buffer stock not only for the two reasons that I have given before but this is also the only sensible course in which it can be done.

This again brings us to the question of price which has been, of course, a very political and controversial issue, sometimes justified and sometimes not so. I would only like to plead with the Government that you connot have a season-to-season approach and you cannot keep the issue hanging for a long period of time for the sustained and scientific development. Not only technology and inputs are required, but the country and the farmers have got to be told, say, in the next 10 years from now, how much acreage depending upon the increase in productivity and improvement in other production aspects, should be set aside because if you have too remunerative a price for sugarcane, a situation might result that there is too much of glut in the market. That is neither good for the industry nor for the farmers. Therefore, there has to be a proper sense of planning in this particular field not only about the quantity of sugarcane produced every year but also in terms of acreage. If you like, you can spell it out. You have to create conditions so that neither shortages nor excesses take place in the field of sugarcane which is likely to bother you for a great deal of time.

There is one more aspect also which is not directly related to our present discussion and that is about the utilisation of bagasse. As the Government knows, bagasse is presently being burned in all sugar mills just as fuel. For a variety of historic reasons, bagasse has continued even now to be used as fuel for the boilers in quite a few factories which are away from the collieries and the sources of fuel. Calling upon the experience of the hon. Minister when he was presiding over the Industry Ministry for quite a number of years, due to national demands. I feel we have to think of having an integrated approach so that bagases is not used as a fuel but as a raw material for the paper and pulp industry. There should be an integrated approach. This is not only likely to remove shortages of paper and pulp in this country...

AN HON. MEMBER : Molasses also.

SHRI N. K. SOMANI : Yes, molasses also ; all these byproducts. The optimum use of molasses and the optimum use of bagasse has got to be developed and the Government should not be satisfied just by an action which is related to sugarcane and sugar production.

I would like to plead with the hon. Minister that before long he should have a discussion or a consultation within his Ministry and the counterparts in the Industry Ministry and also both the sugar Industry and the paper and pulp industry, and the users of molasses, so that all could put their heads together to see how in the entire national economic exercise the optimun use of the raw materials in other industries could be achieved instead of being burnt as fuel or being wasted...

श्रीमती सावित्री श्याम (आंवला) : सभापति महोदय, चीनी का उद्योग बिहार और उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग है। अकेले यू० पी० में 71 चीनी मिलें हैं और 85,000 व्यक्ति उस उद्योग में किसी न किसी प्रकार लगे हुए हैं। 1936 में इस उद्योग की स्थापना हुई थी। उस दिन से आज तक—आजादी से पहले भी और उस के बाद भी—सरकार द्वारा चीनी और गन्ने के सम्बन्ध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं अपनाई गई है। सरकार की ओर से सदैव एडहाक नीति अपनाई गई है। और वह भी किस समय? जब गन्ने के क्रशिंग का टाइम आ गया, मिलों ने थ्रेटन किया कि मिलें नहीं चलेंगी और गन्ना खेतों में सूखने लगा, तब कीमतें निर्धारित की गई। वे कीमतें किसी उसूल या प्रिंसिपल के आधार पर नहीं, बल्कि एडहाक बेसिस पर निर्धारित की गई।

18.26 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

सेन कमीशन ने और बातों के अलावा यह कहा था कि गन्ने की कीमतों और चीनी की कीमतों में एक अनुपात होना चाहिए और केन-ग्रोअर, किसान, को उस अनुपात के अनुसार कीमतें मिलनी चाहिए। जहां तक इस बात का संबंध है, आज तक उस कमीशन की रिपोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जब से देश में एक मिक्स्ड इकानोमी की स्थापना हुई है, तब से इस प्रिंसिपल का सब से अधिक दुरुपयोग हुआ है—प्राईवेट सैक्टर में भी और पब्लिक सैक्टर में भी।

प्राईवेट सैक्टर ने सरकार के साधनों, रीसोर्सिज, से अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश की। उस ने एक्साइज ड्यूटी माफ कराई, एमार्टाइजेशन का रीबेट लिया, उद्योग के एक्सटेंशन और एक्सपेंशन के लिए सुविधाएं प्राप्त कीं। लेकिन उस ने दृष्टिकोण को भुला दिया कि जो किसान और मजदूर रा मैटीरियल को उत्पन्न करते हैं, जो रा मैटीरियल से कनज्यूमर गुड्ज बनाते हैं, उन के प्रति भी उस की कोई सामाजिक जिम्मेदारी है। इस बात को भुला कर उस ने केवल अपने निजी लाभ को सामने रखा। आज तक वह निजी लाभ ज्यों का त्यों चल रहा है। इस रवैये से चीनी मिल-मालिकों ने मैक्सिमम फायदा उठाने की कोशिश की है। अब समय की मांग है कि इस उद्योग को सरकार अपने हाथ में ले ले, इस का नैशनलाइजेशन करे, या इस को को-आपरेटिव सैक्टर में चलाये और वह बिना मुआवजा दिये हुए ऐसा करे।

सदस्य कहते हैं कि चीनी के कनजम्प्शन को बढ़ाया जाये। वह कैसे बढ़ाया जाये? एक तरफ चीनी की कीमत बढ़ती है और दूसरी तरफ खरीदने वालों की परचेजिंग पावर घटती है। चीनी की कनजम्प्शन बढ़ने के बजाये वह दस परसेंट घटी है। एक तरफ देश में चीनी की खपत घटी है और दूसरी तरफ उस का एक्सपोर्ट घटा है। 1966-67 में 4 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ था, जब कि 1967-68 में 1.25 लाख टन का। इस का मतलब यह है कि न हम को बाहर का मार्केट मिल रहा है और न देश में खपत है। सरकार को इस पूरे उद्योग को अपने हाथ में ले कर एक आयोग द्वारा इन सब समस्याओं का विश्लेषण करना चाहिए। जो कमीशन अभी नियुक्त हुआ है, उस की रिपोर्ट आने में देर लग सकती है।

अभी सरकार को गन्ने की कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। पिछले साल उस ने साढ़े नौ रुपये निर्धारित की थी, लेकिन वह कीमत किसी मिल वाले ने नहीं दी। सरकार एक कीमत की घोषणा करती है, लेकिन वह मिल वालों के दबाव के आगे झुक जाती है और उस के बाद अपनी कीमतों को स्वयं बदल देती है। अगर इस साल भी गन्ने की कीमतों को ठीक ठीक

[श्रीमती सावित्री श्याम]

निर्धारित नहीं किया गया, तो देश में बड़ा भारी एजीटेशन होगा । श्री काशीनाथ पाण्डेय आधी बात करते हैं । एक तरफ वह केन-ग्रोअर्ज"की बात करते हैं और दूसरी तरफ मिल वालों की बात करते हैं । दोनों बातें साथ नहीं चल सकती हैं । देश में प्राडक्शन जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन वह किस तरह बढ़े, इस के लिए सरकार को एक ग्रायोग नियुक्त करना चाहिए, जो इस विषय में सुझाव दे ।

मेरी मांग है कि देश में गन्ने के एरिया को कम किया जाए । देश में गन्ने के इतने बड़े एरिया की जरूरत नहीं है दूसरे कैश क्राप्स को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । मिसाल के तौर पर काटन के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए । देश में उस की खपत काफी घट रही हैं, क्योंकि उन की कीमतें शूट अप कर रही हैं और देश में परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है ।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्रीमती सावित्री श्याम : सभापति महोदय, अपनी बात मुझे कहने तो दीजिए ।

सभापति महोदय : नहीं, आप देखिए, हमारे पास 15 बोलने वाले हैं और 7 बजे हम को इसे बन्द कर देना है । अगर एक एक आदमी इतना टाइम लेगा तो कैसे पूरा होगा ? फिर मिनिस्टर साहब जवाब भी देने वाले हैं । इसीलिए तीन चार या पांच मिनट से ज्यादा मैं किसी को नहीं दे रहा हूं (**व्यवधान**)...

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) With your permission, Sir, I move :

> "That the time for the debate be extended by half an hour."

सभापति महोदय : सवाल यह है कि अगर साढ़े सात बजे तक भी हम बैठें तो उस में अगर यह इतने बड़े बड़े लेक्चर होंगे तो हम कुछ नहीं कर पायेंगे । आप लोगों ने साढ़े सात तक समय मांगा है । तो साढ़े सात बजे चाहे मंत्री जवाब दिए हों चाहे न दिए हों, हम हाउस को उठा देंगे ।

श्रीमती सावित्री श्याम : दूसरी बात 22 करोड़ रुपया क्रेन ग्रोग्रर्स का जो शुगर मिलों के पास है उसको दिलाने की पहले कोशिश कीजिए, तब मिलों के हक में आगे को अपना कदम बढ़ाइये । दूसरे, जो डेवेलपमेंट सेस इकट्ठा किया गया वह किसानों से इकठ्ठा किया गया श्रौर किसानों के हित में लगाने के लिए इकट्ठा किया गया । उस का आज तक पूरा पूरा हिसाब सदन को मिलना चाहिए कि उन मिलों के पास कितना डेवेलपमेंट सैस का रुपया है और किस किस तरह से उन्होंने इस रुपए का उपयोग किया है ।

अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो सिक मिल्स हैं उन को बिलकुल बन्द कर देना चाहिए और जो अच्छी मिलें हैं उन को लेकर चलाइए, कोआपरेटिव सेक्टर में चलाइये और किसी प्रकार का मुआवजा देने की बात मत सोचिये ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) श्रीमन, एक तो मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि पिछली 25 तारीख को मैं ने यह निवेदन किया था कि गन्ने का जो वर्तमान मूल्य है वह इतना असंतोष जनक है और इतना अपर्याप्त है कि किसान यह समझता है कि उसे सारी चीजें बाजार से बड़े मंहगे दामों में खरीदनी पड़ती हैं लेकिन उसे अपनी पैदावार का मूल्य बिलकुल कम मिल रहा है । जितना औद्योगिक उत्पादन देश में है उस का मूल्य निरंतर बढ़ रहा है और दूसरी चीजों के दाम भी निरंतर बढ़ रहे हैं परन्तु उनके मुकाबिले में किसानों का गन्ना बहुत सस्ता है तो किसानों की कमर टूट रही है और किसानों को आज

कोई यह विश्वास नहीं दिला सकता कि उस के साथ न्याय हो रहा है। वह समझता है कि उस के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तो एक तो आप इस पर कृपया दोबारा विचार कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश का किसान जीवित रहे, इस देश का किसान पनपता रहे और वह अपने खेत पर निश्चिन्त हो कर लगा रहे।

दूसरी बात अभी हमारी बहन जी ने कहा कि गन्ने का एरिया कम करना चाहिए। उस की जगह दूसरी वैकल्पिक खेती करनी चाहिए और उन्होंने सुझाव दिया कि गन्ना बोना बन्द करके किसान कपास बोया करे। लेकिन हमारी बहन जी को शायद पता नहीं है कि गन्ना कहां उगता है, किस खेत में पैदा होता है। जहाँ गन्ने का उत्पादन होता है, मैं बहन जी से कहता हूं कि वह अपने सारे साइंटिस्टों को ले कर चलें और वहां कपास पैदा करके दिखला दें। जहां गन्ना पैदा होता है वहां कपास पैदा होता ही नहीं क्योंकि जहाँ नमी के इलाके हैं वहां कपास पैदा नहीं हो सकता। और फिर आप देखें, किसान ने गेहूँ पैदा किया तो गेहूं की पैदावार से भी वही प्राबलम सामने आ गई कि गेहूं भी बाजार में सस्ता बिक रहा है। किसान अगर यह समझता है कि चीनी की कमी है इसलिए गन्ने की पैदावार उस ने बढ़ाई तो गन्ने के भाव और गुड़ के भाव की यह हालत हो गई। और यदि किसान यह समझता है कि हमें गेहूं ज्यादा बोना चाहिए, उस ने गेहूं ज्यादा पैदा किया, उसका उत्पादन बढ़ाया तो गेहूँ की कीमत गिर गई। तो अब तीसरी जो चीज बहनजीयह हमारे दूसरे भाई कहते हैं जिस दिन वह उस को बोने लगेगा और उस का उत्पादन बढ़ाएगा उस दिन मंत्री जी बड़ी असहाय अवस्था में खड़े होकर कहेंगे कि हम क्या करें, उत्पादन बहुत बढ़ रहा है, कहां से दें, इस का उत्पादन कम होना चाहिये। एक बार आप देश में उत्पादन•कमी है इस प्रकार का शोर मचाते हैं और किसान जब उत्पादन बढ़ाता है, चीज बाजार में आती है तो आप असहाय होकर यह कहते हो कि उत्पादन ज्यादा हो गया, हम क्या करें? यह क्या आप की प्लानिंग है? क्या आप की एकोनामी है? किस तरह से आप की अर्थ व्यवस्था देश में चलेगी। इस लिए में यह कह रहा हूं कि गन्ने का मूल्य बढ़ा कर किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए।

इसी के साथ साथ किसानों की बकाया राशिके सम्बंध में भी 25 नवम्बर को मैंने मंत्री महोदय से कहा था। उन्होंने उस दिन कहा था कि 21 करोड़ रुपया किसानों का उन की तरफ बाकी है। यानी जितना गन्ना किसान ने दिया उस का जो मूल्य बैठना है उस का 7 परसेंट अभी किसानों से मिलों से मिलना बाकी है। उस को दिलाने के लिए आपने कोई ठोस और कारगर उपाय नहीं किया। मैं समझता हूं कि उस के लिए जो इंडियन शुगर मिल्ल एसोशिएशन ने मांग कही हैं वह बड़ी उचित मांग है। उन का कहना है कि उन के पास स्टाक ज्यादा जमा हो जाता है, और उनके पास इतना पैसा नही होता। वह कहते हैं कि हमारे स्टाक के अगेंस्ट हम को बैंकों की लिमिट बढ़ाने की इजाजत देनी चाहिए। पिछले साल लिमिट बढ़ाई थी 210 करोड़, अब वह चाहते हैं वह लिमिट 450 करोड़ तक बढ़ाई जाए खास कर अप्रैल और मई के महीने में। मैं समझता हूं कि यह उन की उचित मांग है। वह कहते हैं कि हम ने भारत सरकार को भी लिखा, रिजर्व बैंक को भी लिखा लेकिन जवाब नहीं मिला है। मैं समझता हूं इस पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए क्योंकि इस में किसान का इंटेरेस्ट है। अगर उनके पास पैसा होगा तो वह किसानों को पे कर सकेंगे और अगर पैसा ही नहीं होगा तो कहां से पे करेंगे?

इस सिलसिले में मैं एक बात और यह

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

कहना चाहता हूं कि आप जितना कोटा रिलीज करते हैं...

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : चेयरमैन महोदय, बड़े दुख की बात है कि * * किसान के लिए इतनी बेरुखी...

सभापति महोदय : यह रेकर्ड पर नहीं जाएगा जो उन्होंने कहा। आप बोलते हैं हाउस के लिए, मैम्बर के लिए और गवर्नमेंट के लिए। यह रेकर्ड पर नही जाएगा। ...(**व्यवधान**) ..

श्री रणधीर सिंह : ...** मैं आल इंडिया रेडियो की बात करता हूं, एक भी आदमी नहीं है

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय से बात कीजिए आल इंडिया रेडियो के बारे में। ...(**व्यवधान**)...आल इंडिया रेडियो के बारे में कहना है तो आप के मंत्री हैं उन को कहिए।

श्री रणधीर सिंह :...**

सभापति महोदय : देखिए यहाँ सब मेम्बरों को पे किया जाता है, वह इसलिए आते हैं कि हाउस में बैठे लेकिन कितने मेम्बर बैठे हैं? ...(**व्यवधान**)...

श्री रणधीर सिंह : हम इस बात को बेहद प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग किसानों के दुश्मन हैं, सब दिखावटी बातें हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : मैं कह रहा था कि सरकार जो महावारी कोटा मिलों के लिये रिलीज करती है, उस में भी सरकार को देखना चाहिए कि जितने कोटे की खपत है, उतना रिलीज करना चाहिए। मान लीजिए कि तीन लाख टन की जरूरत है, लेकिन रिलीज कर देते हैं 6 लाख टन, तो इससे मुश्किल पैदा हो जाती है, उस के व्यावहारिक रूप को देखकर जितनी खपत हो, उस के अनुसार रिलीज करना चाहिए।

यह ठीक है कि देश में जो चीनी खानेवाले लोग हैं, उन को चीनी सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए, लेकिन चीनी को किसानों की कीमत पर सस्ता नहीं करना चाहिए, चूंकि चीनी सस्ती देनी है, इसलिए किसानों का गन्ना सस्ता कर दो, यह सही नीति नहीं है इस के लिए आप कोई दूसरा उपाय कीजिए, एक्साइज ड्यूटी को घटाइये या कोई दूसरा तरीका अपनाइये, लेकिन काश्तकारों के गन्ने को इस आधार पर सस्ता ना कीजिए, उस को पूरा दाम मिलना चाहिए। मेरी मांग है कि गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, उस को गन्ने का बाकी पैसा दिलाया जाए और सस्ती चीनी के लिए गन्ने को सस्ता न किया जाय।

श्री बेनी शंकर शर्मा (बांका) : सभापति महोदय, जहां सरकार हर साल अक्तूबर में अपनी शुगर पालिसी निर्धारित कर घोषणा करती थी, वहां इस साल आज 16 दिसम्बर हो गया है और सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चुनावों के साथ इस का कोई खास सम्बन्ध है, सभापति महोदय, मेरे पास 30 नवम्बर तक के फिगर्स हैं—उस दिन तक करीब करीब 3 लाख 13 हजार टन चीनी पैदा हो चुकी है। मिल मालिक एवं किसानों के मन में आज भय व्याप्त है कि पता नहीं इसके सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी। उन की कुछ समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जितनी जल्द हो सके सरकार अपनी शुगर पालिसी की घोषणा करें।

दूसरी बात अभी जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, मैं उस पर आना चाहता हूं। हमारे सामने समस्या है कि आया चीनी डी कंट्रोल की जाय, क्योंकि पैदावार काफी हो रही है और जब पैदावार काफी होती है तो कंट्रोल रखने की कोई तुक नहीं है, या उस पर फिर से पूरा कन्ट्रोल किया जाय या पार्शियली डी कन्ट्रोल हो। ये ऐसी चीजें हैं जिन पर तुरन्त निश्चय करना चाहिये। जहां तक मेरी

पार्टी का सम्बन्ध है हम लोग बराबर इस बात के हिमायती रहे हैं कि किसी वस्तु पर किसी प्रकार का कन्ट्रोल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कन्ट्रोल की बजह से ही देश में ब्लेक मार्केट होती है जिससे ब्लेक मनी आता है और फिर मनी को बाहर निकालने के लिए हम कमीशन बनाते हैं। यह ऐसा विशस सर्किल है, जिस का कोई अन्त नहीं है किन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं पार्शियल डी कन्ट्रोल का ही समर्थन करूंगा। आज चीनी के व्यापार में एक बड़ी विचित्र समस्या पैदा हो रही है और वह समस्या यह है कि हमारे पास जो स्टाक है 21 लाख टन हम ने कैरी ओवर किया है, 40 लाख टन हम इस साल में बना लेंगे, इस तरह से इस साल में हमारे पास 61 लाख टन चीनी होगी, जब कि हमारी इंटरनल कन्जम्पशन 34 लाख टन ही होगी, साढ़े तीन लाख टन चीनी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह से फिर भी हमारे पास साढ़े-तेईस-लाख टन का काफी स्टाक रह जायगा। इस चीनी का हम क्या करें—यह समस्या है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम इस के बारे में वह जल्द से जल्द कुछ निश्चय करें क्योंकि इस 23 लाख टन चीनी की जो कीमत होती है, हमारा वह रुपया बेकार पड़ा हुआ है, जो कोई काम नहीं आ रहा है—चाहे वह किसान का रुपया हो या व्यापारियों का रुपया हो या बैंक का रुपया हो। इस लिए हमें इस चीनी की किस तरह से खपत करनी चाहिये...इस के बारे में शीघ्र सोचना चाहिए।

अभी हमारे एक मित्र ने बफर स्टाक का सुझाव दिया है, मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूं। सेन कमीशन ने भी 10 लाख टन का बफर स्टाक बनाने का सुझाव दिया है, इस से जहां तहां चीनी के स्टाक की पोजीशन को ईज करने में सहायता मिलेगी। वहां इस से यह लाभ भी होगा कि जब कभी हमारे यहां चीनी की कमी होगी, जैसे कभी पैदावार ठीक न हो या गन्ने की खेती में कीड़े लग जांय और पर्याप्त उत्पादन न हो, तो इस स्टाक को काम में लाया जा सकेगा तथा व्यापारियों को ब्लेक मार्केट करने पर चीनी का दाम बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमें चीनी कों एक्सपोर्ट बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। आज हम साढ़े तीन लाख टन चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रयत्न करना चाहिये कि कुछ और अधिक चीनी एक्सपोर्ट हो ताकि चीनी का स्टा कम हो सके।

परन्तु सब से बड़ा प्रश्न आज यह है कि किसानों न मिलों को जो गन्ना सप्लाई किया था, उस का 1 वर्ष से, 2 वर्ष और कहीं कहीं तो 3 वर्ष से रुपया नहीं मिला है। उधर मिल मालिकों के पास पैसा नहीं क्योंकि चीनी का स्टाक पड़ा हुआ है। इस लिए शगर इण्डस्ट्री ने जो डिमाण्ड की है कि उन्हें साढ़े चारसौ से 500 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट फैसिल्टी उन मिलनी चाहिए वह फैसिलीटी को दी जानी चाहिए।

जहां तक बेज बोर्ड का ताल्लुक है—आप जानते हैं कि इण्डस्ट्री ने बेज बोर्ड को रिकमेंडेशन को मान लिया है, इस लिए मैं आप से अनुरोध करूंगा कि चीनी की नीति निर्धारित करते समय बेज बोर्ड ने मजदूरों को जो पैसा देने की सिफारिश की है, उस को भी अपने विचाराधीन रखेंगे, क्योंकि यदि आप उस पर विचार नहीं करते, और अगर इण्डस्ट्री मजदूरों का इतना पैसा नहीं दे सकती तो इस उद्योग में भी वैसी ही स्थिति पैदा हो जायगी, जो आज जूट उद्योग में पैदा हो रही है।

जैसा अभी आपने कहा था कि चीनी में कन्ट्रोल हो, या डी-कन्ट्रोल हो या पार्शियल कन्ट्रोल हो मैं समझता हूं कि अगर हम डी-

[श्री बेणी शंकर शर्मा]

कन्ट्रोल कर देते हैं सो साथ ही साथ जो केन प्रोडयूसर्ज है, गन्ना बेचने वाले हैं, उन को कितना दाम मिले, इस को तय नहीं कर सकेंगे। उन को ठीक दाम मिले, इस दृष्टि से आप को चीनी का दाम निर्धारित करना पड़ेगा। इस लिए मेरी दृष्टि में जो आप की पार्शियल डी-कन्ट्रोल की नीति चली आ रही है, वह ठीक है और मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उस के लिये भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री जगजीवन राम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस ने कम से कम चीनी उद्योग में ब्लेक मार्केट को खत्म कर दिया है।

श्री तुलशी दास जाधव (बारामती) : सभापति महोदय, मेरी पहली बिनती यह है कि जैसा रणधीर सिंह जी ने कहा वह बात सही है कि देश के 85 परसेन्ट लोगों की बात उठी है, * * *

श्री रणधीर सिंह : * * * आल इण्डिया रेडियो का सवाल है, मैं भूख हड़ताल करूंगा-किसानों के साथ यह बेइज्जती क्यों? मैं इस का बहुत बुरी तरह से फील करता हूं, किसानों के साथ बेहद बेइन्साफी है...

श्री तुलशी दास जाधव : आप उन को विरोध भेज सकते हैं, यह आप का अधिकार है...

श्री रणधीर सिंह : * * * आल इण्डिया रेडियो का आदमी होना चाहिये। आज देश के 40-50 करोड़ आदमियों का सवाल है, केन की प्राइसेज का सवाल है। जब 50—100 आदमी वेजेज मांगते हैं, तब यहां रेडियो वाले होते हैं, लेकिन जब 50 करोड़ आदमियों को कीठ कीमत मिले या न मिले—यह मसला आता है तो वे यहां नहीं हैं। मैं यहां से नहीं उठूंगा जब तक रेडियो वाले माफी नही मांगेंगे।

I can't tolerate this.

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Do you think that it is only for the labourers and other businessmen that Parliament is sitting?

SHRI RANDHIR SINGH : I want to say about All India Radio.

श्री तुलशी दास जाधव : सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि इस देश में कम से कम 70 से 75 परसेंट प्रजा काश्तकार हैं—यह उन का सवाल है। शुगर के बारे में मेरे पास जो फिगर्स हैं, उन को देखने से मालूम होता है अभी 38.43 लाख टन का स्टाक पड़ा हुआ है जोकि बिकना है और जिसमें पैसा अटका हुआ है।

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : नहीं नहीं।

श्री तुलशी दास जाधव : 21.83 लाख टन का स्टाक पहले था और अभी का 16.60 लाख टन का स्टाक है। इसमें कुछ कमी बेशी भी हो सकती है। जो प्रश्न किया है उसमें भी आपने कहा है कि स्टाक पड़ा हुआ है। इसके माने ये हैं कि...

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : Nobody will speak.

SHRI RANDHIR SINGH : I am feeling very very much pained. I cannot speak. I am very much overwhelmed and I am moved. What is this? This is the greatest injustice to the peasants of this country. Nobody is there from the All India Radio to record the proceedings of the House.

***Not recorded Vide Chairmanes Orders in col...

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond-Harbour) : They are sitting there. Why is it said a hundred times ?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : They have come only now.

SHRI RANDHIR SINGH :***I am very sorry that nobody from the All India Radio is there. Somebody from there must be present... (व्यवधान).. जब मजदूर का सवाल आयेगा तो बताऊंगा। यह कोई पर्सनल सवाल नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : * * *

*Interruptions** * *

MR. CHAIRMAN : What Shri Ramavatar Shastri and others are saying now—nothing will go on record. (*Interruption*) I will adjourn the House. If it goes on like this, I will adjourn the House.

SHRI RANDHIR SINGH : I want to walk out in protest. I am not going to participate in the debate.This is too much. (*Interruption*) I was saying about the All India Radio. Please do not misunderstand me. The radio people must come here. (*Interruptions*)

SEVERAL HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11 a.m. tomorrow.

18.55hrs.

The Lok Sabha then adjonrned till Eleven of the Clock on Thursday, December 17, 1970/Agrahayana 26, 1892 (Saka).

***Not recorded.